



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931

No. 622]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 786(अ).—राष्ट्रपति द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप-धारा (2) के तहत किए गए निम्नलिखित आदेश को जैसा कि उस धारा के अधीन अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :—

मद्रास उच्च न्यायालय (मद्रुरै में एक स्थायी पीठ की स्थापना) संशोधन आदेश, 2009

राष्ट्रपति, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तमिलनाडु के राज्यपाल तथा मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, मद्रास उच्च न्यायालय (मद्रुरै में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश करते हैं, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय (मद्रुरै में एक स्थायी पीठ की स्थापना) संशोधन आदेश, 2009 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. मद्रास उच्च न्यायालय (मद्रुरै में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 2004 के पैराग्राफ-2 में "नागपट्टिनम" और "पैराम्बलूर" शब्दों को हटाया जाएगा।
3. इस आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रुरै पीठ में नागपट्टिनम और पैराम्बलूर जिले से संबंधित निस्तारण के लिए लम्बित पड़ी कोई अपील, उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन, पुनरीक्षा एवं अन्य कार्यवाही के लिए आवेदन को मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान सीट में अन्तर्गत माना जाएगा।

नई दिल्ली,

26 अक्टूबर, 2009

राष्ट्रपति

[फा. सं. के-11018/5/98-यू एस-1]

श्रीमती भूपिन्दर प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 6 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2009

G.S.R. 786(E).—The following Order made by the President under sub-section (2) of Section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) is hereby published as required by that sub-section :—

The Madras High Court (Establishment of A Permanent Bench at Madurai) Amendment Order, 2009

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the President, after consultation with the Governor of Tamil Nadu and the Chief Justice of the Madras High Court, is pleased to make the following order to amend the Madras High Court (Establishment of a Permanent Bench at Madurai) Order, 2004, namely:—

1. (1) This Order may be called the Madras High Court (Establishment of a Permanent Bench at Madurai) Amendment Order, 2009.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Madras High Court (Establishment of a Permanent Bench at Madurai) Order, 2004, in paragraph 2, the words “Nagapattinam” and “Perambalur” shall be omitted.
3. Any appeal, application for leave to appeal to the Supreme Court, application for review and other proceedings pertaining to the Districts of Nagapattinam and Perambalur pending for disposal in the Madurai Bench of the Madras High Court prior to commencement of this Order shall stand transferred to the principal seat of the Madras High Court.

New Delhi,

The 26th October, 2009

PRESIDENT

[F.No. K-11018/5/98-US-I]

Ms. BHUPINDER PRASAD, Addl. Secy.

Note :— The Principal Order, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (i) vide Notification number G.S.R. 446(E) dated the 6th July, 2004.